

ऐसे जीयो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो।
- अज्ञात



बिहार विधानसभा चुनाव

चूंकि यह चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक-एक व्यक्ति और राज्य की समूची जनता की जिंदगी का सवाल है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रत्याशी ही नहीं, कार्यकर्ता, चुनावकर्मी और वोटर भी इस मोर्चे पर एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।

रवि वर्मा।

तमाम अटकलों के बाद आखिर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हालांकि आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार संबंधी निर्देश जारी कर यह संकेत पहले ही दे दिया था कि चुनाव टालने के मूड में वह नहीं है, फिर भी महामारी के प्रसार में अपेक्षित कमी न होने से यह आशंका कहीं न कहीं बनी हुई थी कि आखिरी पलों में उसे चुनाव टालने का फैसला न लेना पड़ जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लगभग समानांतर होने वाले ये चुनाव कोरोना कालीन दुनिया की दो सबसे बड़ी चुनावी कवायदों में एक होने वाले हैं। महामारी के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में हालात कई अन्य राज्यों से बेहतर हैं, फिर भी बीमारी को और फैलाए

बिना सुरक्षित ढंग से चुनाव करा लेना निर्वाचन आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। इस संबंध में मतदान की अवधि एक घंटा बढ़ाने से लेकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही मतदान की व्यवस्था करने तक उसके द्वारा जारी तमाम दिशा निर्देश खासे अहम हैं। देखना यही है कि व्यवहार में इन पर अमल किस हद तक सुनिश्चित हो पाता है। चूंकि यह चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक-एक व्यक्ति और राज्य की समूची जनता की जिंदगी का सवाल है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रत्याशी ही नहीं, कार्यकर्ता, चुनावकर्मी और वोटर भी इस मोर्चे पर एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। जहां तक चुनावी लड़ाई की बात है तो वर्चुअल रैलियों का आगाज

काफी पहले हो जाने के बावजूद दोनों खेमों में मोर्चेबंदी का मामला बुरी तरह उलझा हुआ है। तय है तो बस इतना कि इस लड़ाई में एक तरफ जेडीयू और बीजेपी होंगी तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस।

इन पार्टियों का आपसी सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ है और यह भी तय नहीं है कि दोनों खेमों के बाकी सहयोगियों की इन चुनावों में क्या भूमिका होगी। अब तक खुद को विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा बताने वाले आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि वे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ

एनडीए खेमे में एलजेपी ने साफ किया है कि पार्टी चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट घोषित करके मैदान में उतरने का विचार रखती है। यानी अभी स्पष्ट नहीं है कि इन दलों की ताकत अंततः किसके पक्ष में और किसके खिलाफ काम आएगी। इसके अलावा पिछले तीन दशकों में बिहार विधानसभा का यह पहला चुनाव है जिसमें लालू प्रसाद यादव की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होगी। ये चुनाव यह भी बताएंगे कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के इर्दगिर्द उभरा बिहारी अस्मिता का मुद्दा ज्यादा कारगर रहेगा या प्रवासी मजदूरों की तकलीफों का ब्योरा। यह भी कि बिहारी वोटरों में 'जंगल राज' की यादें ज्यादा गहरी हैं या मौजूदा शासन से उम्मीदें टूटने की मायूसी।

धार्मिक महत्व

अशोक वोहरा।
भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसका जल घर में शीशी या प्लास्टिक के डिब्बे आदि में भरकर रख दें तो

धर्म-दर्शन



बरसों तक खराब नहीं होता है और कई तरह के पूजा-पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी आम धारणा है कि मरते समय व्यक्ति को यह जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सफल बनना चाहते हो सिर्फ इस वजह से आपके जीवन में कभी सफलता नहीं आएगी। यदि आप निचे दी गयी आदतों को नहीं अपना सकते हो तो आपका जीवन सामान्य ही रह जायेगा और आप अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी आप अपने आस-पास सफल लोगों को देखते हैं, तब ये बात कभी नहीं भूले की वह भी इन्हीं ज्ञान की बातों को मानते हैं और उन्हें अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयास करते हैं।

संपादकीय

दो मोहम्मदों के बीच

2015 में यमन में उनके 52 फौजी हूती विद्रोहियों के मिसाइली हमले में एक ही दिन मारे गए। इजिप्ट में वे बड़ा निवेश ही नहीं कर रहे, वहां के सत्ता के खेल में भी उलझे हुए हैं। लीबिया में वे संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार के खिलाफ वहां के सैनिक जुंटा को सपोर्ट कर रहे हैं। अबू धाबी के युवराज मोहम्मद बिन जाएद (एमबीजेड) सरुदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) की तरह खुद को यूएई का प्रभावी शासक मानने लगे हैं और यह जुगलजोड़ी न सिर्फ अरब दायरे के लिए बल्कि खुद के लिए भी रोज कोई न कोई नई मुश्किल खड़ी कर रही है। 2005 से 2020 के बीच, सिर्फ 15 साल में यूएई की आबादी 41 लाख से बढ़कर 99 लाख, लगभग ढाई गुना हो गई है तो इसके लिए इस देश की बढ़ती समृद्धि जिम्मेदार है। अमीरी से आबादी और आबादी से अमीरी, ऐसा 'सु-चक्र' भला दुनिया में कितनी बार देखने को मिला है? कुल आबादी में कोई साठ फीसदी दक्षिण एशियाई हैं, जिनका बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह कि संसार का कोई देश, कोई जातीयता ऐसी नहीं है जिसके लोग यूएई के किसी भी शहर में आपको न दिख जाएं। अपनी इस ताकत का फायदा यहां के शासकों ने अपने कारोबार का बहुलीकरण करके उठाया है, जो तेल-निर्भर खाड़ी क्षेत्र के लिए एक दुर्लभ बात है। लेकिन ताकत का दूसरा इस्तेमाल वे 'अरब स्प्रिंग' के बाद से हर कहीं पंगा लेने में करने लगे हैं, जिससे यूएई का जोखिम बढ़ गया है। खाड़ी क्षेत्र में यूएई निश्चित रूप से एक चटख उम्मीद बनकर उभरा है, लेकिन उसकी सफलता कितनी टिकाऊ सिद्ध होगी, यह उसके शासकों की सदबुद्धि पर निर्भर करता है।

कोरोना वायरस के प्रकोप से अभी हर देश अपने ही खेल आयोजनों को टालने में जुटा है, किसी और देश का बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट अपने यहां कराना यकीनन कड़ा कलेजा मांगता है।

कोस्ट ऑफ पाइरेट्स

चंद्रभूषण।।

आईपीएल आयोजित करने के लिए जुलाई में तीन देशों के प्रस्ताव बीसीसीआई के सामने थे। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)। कोरोना वायरस के प्रकोप से अभी हर देश अपने ही खेल आयोजनों को टालने में जुटा है, किसी और देश का बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट अपने यहां कराना यकीनन कड़ा कलेजा मांगता है। फिर भी इन देशों ने आईपीएल कराने का प्रस्ताव बीसीसीआई के सामने रखा तो इसके पीछे दो वजहें थीं। एक तो इससे भारी कमाई होना तय था, दूसरे इन तीनों देशों में कोरोना के नियंत्रित रहने की संभावना औरों से ज्यादा थी। बीसीसीआई के लिए भारत के बाद पहली प्राथमिकता यूएई ही हो सकता था क्योंकि न सिर्फ 2014 में वहां आईपीएल आयोजित किया जा चुका है, बल्कि हजार मामलों में भारत के जेहनी और कारोबारी तार दुबई, अबू धाबी और शारजाह ही नहीं, समूचे यूएई के साथ जुड़े हैं। अभी जब हम आईपीएल मैचों के दौरान फारस की खाड़ी के इन तीनों तटवर्ती शहरों के जगमग नजारे देख रहे हैं, तब हमें यह भी पता होना चाहिए कि असल में हम बीती आधी सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक-आर्थिक चमत्कार देख रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी मौजूदा



शकल फरवरी 1972 में ग्रहण की थी। यानी उसे जन्मे अभी पचास साल भी नहीं हुए हैं। इस इलाके की गिनती तब तक दुनिया के दरिद्र इलाकों में हुआ करती थी। यूएई में शामिल सातों रियासतें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास अल खैमा, फुजैरा, अजमान और उम्म अल क्वैन जिस समुद्र तट को छूती हैं, उसका नाम सैकड़ों साल तक 'समुद्री डकैतों का तट' (कोस्ट ऑफ पाइरेट्स) था। हालांकि अमीरातियों की नीयत पर शक न करते हुए अभी इतना ही कहा जाता है कि दुबई और अबू धाबी की पहचान 1972 तक मछुआरों की बस्ती जैसी थी, व्यापारिक जहाज उधर जाने से बचते थे। इन रियासतों की दूसरी पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इनके शासकों की रंजिशें थीं। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्नीसवीं सदी में इनके साथ कई समझौतों पर दस्तखत किए और इन्हें 'समझौते

वाली रियासतें' (ट्रिब्युल स्टेट्स) कहकर अपनी सरपरस्ती में ले लिया। 1971 के अंत में ब्रिटेन ने इन्हें आजाद किया लेकिन इनके साथ असल चमत्कार 1973 के अरब-इजराइल युद्ध के बाद हुआ, जब कच्चे तेल की आसमानी कीमतों ने न सिर्फ इनकी आर्थिक हैसियत ऊंची कर दी, बल्कि इसके थोड़ा ही पहले तेल कंपनियों के सरकारी मालिकाने में चले जाने के कारण यूएई सरकार का रुतबा भी बढ़ा दिया। यहीं से यूएई की आर्थिक सफलता की कथा लिखी जानी शुरू हुई, जिसका पहला अध्याय यह था कि कॉरपोरेट टैक्स के अलावा यहां किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। 5 प्रतिशत वैल्यू ऐडेड टैक्स भी (वैट) यूएई में 2015 से शुरू हुआ है।

दुबई से हमारा जो विशेष परिचय खबरों और सिनेमा के जरिये बना है— सोने की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा, उसका संबंध भी यूएई की इस टैक्सेशन पॉलिसी से ही है। सोने की बुनियादी कीमत पूरी दुनिया में एक होती है। सिर्फ टैक्स की दरें उस कहीं महंगा कहीं सरस्ता बनाती हैं। बहरहाल, दुबई का चमत्कार सिर्फ उसकी कर नीति से नहीं जुड़ा है। मात्र 14 लाख की स्थानीय आबादी वाला यह देश एक छोर से देखने पर पिछड़े मिजाज की निरंकुश तानाशाहियों का समूह लगता है, लेकिन आप इसके मंत्रालयों की सूची— और उनके कुछ कामों पर भी— नजर डालें तो इसकी रौशनखयाली देखकर दंग रह जाएंगे।

यूईपीएल नवताल- 5370				* * * * *			
3	9		1				
5	4		6	8		1	3
	1		7		9	5	
8	9		5	3		4	7
6	1		4	9		2	3
	3	4		1		8	
7	5		8	3		2	4
		6				7	9

अपना ब्लॉग

इस्लामी दुनिया का पहला हिंदू मंदिर

मोहन। संयुक्त अरब अमीरात संसार का वह इकलौता देश है, जहां बाकायदा एक सहिष्णुता मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस) है। अबू धाबी में इस्लामी दुनिया का पहला हिंदू मंदिर यू ही नहीं बन रहा। इसके पीछे पराई संस्कृतियों के लोगों से भरे इस देश की सामाजिक नीति है। हमारे पड़ोसी भूटान की तरह यूएई में भी एक प्रसन्नता मंत्रालय है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री भी वहां काम कर रही है। नई पीढ़ी के लिए अलग मंत्रालय के बजाय एक नेशनल यूथ काउंसिल यहां काम करती है, जिसका एक प्रतिनिधि देश की कैबिनेट में बतौर 'मिनिस्टर ऑफ यूथ' शामिल रहता है। और तो और, एक मिनिस्ट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज भी यूएई में सक्रिय है, जो विभिन्न चुनौतियों का समाधान ढूँढने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए सुझाव देती है। असल में सारे मंत्रालयों का काम वहां सुझाव देने तक ही सीमित है। सरकारी कामों के लिए मोहर मारने का काम शाही खून वालों से बचे तो कोई और करे।

हूहो गई पद लेने गया था पदविहलेकर आ गया...

